क्या रहेगा हरियाणा चुनाव में.....

पेज एक का शेष

4. हिसार लोकसभा सीट

यह सीट कभी भजनलाल का गढ़ थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि स्व. भजनलाल के परिवार से खड़े भव्य विश्नोई की कहीं कोई गिनती ही नहीं है। इस सीट पर भाजपा के बिजेंद्र सिंह और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के दुष्यंत चौटाला का सीधा मुकाबला है। दुष्यंत यहां 2014 में मोदी लहर के बावजूद जीते थे। इस बार वह फिर से मैदान में हैं। यहां पर दो जाटों की सीधी लड़ाई है लेकिन कुल मिलाकर यहां दुष्यंत का पलड़ा भारी है। दरअसल, दुष्यंत जाट मतदाताओं को यह समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि जाट लीडरशिप के असली हकदार वही हैं। बिजेंद्र सिंह आईएएस हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बिरेंद्र सिंह के बेटे हैं। इस परिवार का पूरा खानदान सांसद-विधायक है। किसानों के मसीहा कहलाने वाले सर छोटूराम का नाम जुड़ा होने का फायदा भी बीरेंद्र सिंह को मिलता रहा है। लेकिन हिसार लोकसभा चुनाव में दुष्यंत ने इस परिवार की सारी हेकड़ी निकाल दी है। बिजेंद्र सिंह अगर हारते हैं तो उसकी एक वजह यहां भाजपा की अंदरुनी उठापटक भी होगी। भाजपा के जाट नेता और मंत्री कैप्टन अभिमन्यु किसी भी हालत में बिजेंद्र सिंह को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते।

5. सिरसा लोकसभा सीट

यहां मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष

अशोक तंवर और अफसर से भाजपा नेता बनीं सुनीता दुग्गल के बीच है। इस लोकसभा सीट पर फैसला डेरे करते हैं। यहां कोई फैक्टर काम नहीं करता, न मोदी और न राष्ट्रवाद। जेल में साज काट रहे राम रहीम समेत कई बाबाओं के डेरे सिरसा की राजनीति को संचालित करते हैं। डेरों का झुकाव इस बार कांग्रेस की तरफ है। पर्चा भरने से लेकर अब तक कांग्रेस के तंवर अपने विरोधी उम्मीदवार पर भारी पड़ रहे हैं। दुग्गल को लोग सिरसा शहर तक में नहीं जानते। भाजपा प्रत्याशी को यहां पहचान के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह यह सीट कांग्रेस के पाले में आसानी से जाती हुई दिखाई दे रही है।

6. भिवानी लोकसभा सीट

इस सीट पर जीत-हार की भविष्यवाणी खतरनाक है। इस जोखिम के बावजूद यहां कांग्रेस की श्रुति चौधरी बाकी प्रत्याशियों पर भारी पड़ रही हैं। दरअसल यह सीट महेंद्रगढ़ और भिवानी को मिलाकर बनी है। महेंद्रगढ़ में जहां यादव मतदाता ज्यादा हैं तो भिवानी में जाट मतदाता ज्यादा हैं। पूर्व सीएम और हरियाणा को खड़ा करने वाले स्व. बंसीलाल की पोती श्रुति ने 2009 में यहां से जीत हासिल की थी लेकिन 2014 में वह भाजपा के चौधरी धर्मवीर से हार गई थीं। भाजपा ने इस बार धर्मवीर को फिर से टिकट दिया है। लेकिन धर्मवीर इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि श्रुति के लिए यहां का मैदान आसान लग रहा है।

7. अंबाला (रिजर्व) लोकसभा सीट

यहां पर कांग्रेस की शैलजा का पलड़ा भारी है। उनके मुकाबले भाजपा से रतन लाल कटारिया हैं। शैलजा लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रही हैं और कटारिया को कई बार हरा चुकी हैं। स्थानीय मुद्दे कटारिया के खिलाफ जा रहे हैं। उनके मुकाबले शैलजा की छवि ज्यादा अच्छी है। कटारिया को सिर्फ मोदी नामक करिश्मे का सहारा है जबकि शैलजा अपने काम की वजह से जीत सकती हैं।

8. करनाल लोकसभा सीट

यहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजय भाटिया को भाजपा टिकट दिलाया है। भाटिया को जिताने के लिए खट्टर को अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ रही है। इस वजह से संजय भाटिया को सरकारी मशीनरी की भी मदद मिल रही है। कांग्रेस ने यहां से (सोनीपत के गन्नौर से विधायक) कुलदीप शर्मा को मैदान में उतारा है। उनके पिता चिरंजीलाल शर्मा करनाल से सांसद रह चुके हैं। करनाल की छवि ब्राह्मण सीट की भी रही है, पर लगता नहीं कि कुलदीप, भाटिया को टक्कर देने से ज्यादा कुछ कर पायेंगे। यहां भाजपा भारी पड़ रही है।

9. गुड़गांव लोकसभा सीट

यहां पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत का कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव से सीधा मुकाबला है। दोनों अहीरवाल के नेता हैं लेकिन गुड़गांव सीट का फैसला मेवात से होता है। आम आदमी पार्टी ने यहां से महबूब खान नामक शख्स को उतारा है जो कांग्रेस के परंपरागत मेव मुसलमानों के वोट काटने में एक तरह से भाजपा की मदद कर रहा है। इस तरह गुड़गांव सीट भाजपा को जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी पता नहीं किस डर में मेवात के मतदाताओं में यह संदेश पहुंचाने में नाकाम रहे है कि यहां आम आदमी पार्टी एक तरह से भाजपा को जिताने में मदद कर रही है। महबूब खान को मेवात में कोई नहीं जानता। गुड़गांव में कोई नहीं जानता। लेकिन यह प्रत्याशी पैसा पानी की तरह बहा रहा है। जब कोई प्रत्याशी प्रचार में भारी दिखाई देता है तो उस समुदाय के मतदाता भी गुमराह होकर उसी को वोट देते हैं। महबूब खान ने अपना पूरा प्रचार मेवात में ही केंद्रित कर रखा है। अगर कैप्टन अजय यादव मुस्लिम मतों को जाने से रोक सके तो यह सीट उन्हें मिल सकती है लेकिन फिलहाल भाजपा प्रत्याशी यहां भारी पड़ रहा है। एक दिन में कैप्टन कोई चमत्कार नहीं कर सकते।

चुनावी ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक त्रासदी

म. मो. (फ़रीदाबाद)- देश में सन् 1952 से लोकसभा विधानसभा सहित स्थानीय निकायों व पंचायतों के चुनाव हर पाँच वर्ष के लिए होते आ रहे हैं ये बात अलग है कि कई बार चुनाव मध्यावधि भी होते रहते हैं ।

जहाँ लोक सभा व विधान सभा चुनावों का प्रबंध भारत के चुनाव आयोग की देख रेख में रहता है वहीं स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य चुनाव आधिकारी की देख रेख में करवाए जाते हैं । इन चुनावों को करवाने में बैंक ,स्वायत्तशासी विभाग ,सार्वजानिक उपक्रमों, केंद्र व राज्य सरकारों के कर्मचारियों सहित राज्य पुलिस केन्द्रीय पुलिस बालों की तैनाती होती हैं । वैसे तो चुनावों को लोकतंत्र के पर्व के रूप में प्रचारित किया जाता है लेकिन पुलिस व केन्द्रीय पुलिस बल के जवानों को छोड़कर अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए ये चुनाव किसी विपत्ति से कम नही होते हैं । पिछले पाँच वर्षों में राज्य व केंद्र सरकार ने बैंक, सरकारी विभागों आदि में कोई भर्ती नही हुई है इस लिए अब सरकारी कर्मचारियों की कमी के कारण प्राइवेट स्कूल व कालेजों तक के स्टाफ को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया जाने लगा है । चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए अधिकतर कर्मचारी हर तरह के बहाने बनाते हैं जिनसे वे चुनावों की ड्यूटी देने से बच जाएँ हालाँकि कुछ की समस्या वास्तविक भी होती हैं।

'मजदूर मोचा' ने चुनावों को करवाने में सरकारी कर्मचारियों को होने वाली परेशानी के बारे में अनेक कर्मचारियों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वे चुनावी ड्यूटी से डरते नहीं हैं लेकिन चुनाव आयोग व प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही व उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण दो दिन तक एक त्रासदी से गुजरते हैं जिस कारण उन्हें चुनावी ड्यूटी एक विपत्ति से कम नही लगती हैं । चुनाव की घोषित तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व से चुनावी ड्यूटी में लगाये गए कर्मचारियों को चुनाव के लिए प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ हो जाता है चुनावी तिथि से पहले दिन विधानसभा क्षेत्र के अनुसार चुनाव सामग्री आवंटित की जाती है जिन्हें प्रत्येक पोलिंग पार्टी अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए समूहों में जो एक रूट के लिए चार पाँच पोलिंग पार्टी कम से कम होती हैं , के लिए रवाना कर दी जाती हैं । ये पोलिंग बूथ अधिकतर स्कूल कालेज या किसी चौपाल पर बनाये जाते हैं ।

शहरी पोलिंग बूथों पर तो फिर भी कुछ व्यवस्था हो जाती है लेकिन गांवों के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग पार्टी को पूरी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । सरकारी स्कूलों के कमरों में खिड़की दरवाजे तक भी नही होते हैं अन्य सुविधाओं जैसे बिजली पानी पंखा चारपाई की सुविधा तो बहुत दूर की बात है। पोलिंग पार्टी के सदस्यों को चुनाव आयोग उनके पदों की स्थिति के अनुसार समय समय पर खाने रहने के लिए धन राशि देता है इस बार पूरे चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी को 2050- रुपये तथा पोलिंग आफिसर को 1550- रुपये देने के आदेश हैं । पोलिंग पार्टी के कर्मचारियों की सबसे बढ़ी समस्या पोलिंग स्टेशन पर रहने व खाने की व्यवस्था को लेकर होती है जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारी पोलिंग पार्टी को आश्वासन देते हैं कि गाँव का सरपंच व पटवारी उनके लिए सभी तरह की व्यवस्था करेंगे लेकिन वहां कोई नही मिलता है । उन्हें पोलिंग स्टेशन पर न तो खाना मिलता है और न ही सोने के लिए चारपाई मिलती है हाँ पोलिंग स्टेशन पर जिन पुलिस वालों की ड्यूटी होती है उनके लिए सरपंच या पुलिस के दलाल टाइप आदमी खाना पीना व सोने का पूरा प्रबंध कर देते हैं क्योंकि स्थानीय थाने के ही पुलिस कर्मी उनके थाने के अंतर्गत आने वाले पोलिंग बूथों पर लगाये जाते हैं इसलिए हर गाँव व शहर के बूथों पर पुलिस वालों की खूब सेवा होती है। पीठासीन अधिकारी तो पोलिंग स्टेशन को छोड़कर कहीं जा भी नही सकता है और कई जगह पोलिंग पार्टी को पैसे से भी कोई खाना या सोने के लिए साधन नही मिलता है । ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के पोलिंग स्टेशनों पर बहुत होती है शहरी क्षेत्रों में तो खाना होटलों से खरीदकर ले आते हैं । ऐसी विषम परिस्थितियों में पोलिंग पार्टी जागते हुए मच्छरों से जूझते हुए रात काटती है ऊपर से उन्हें अगले दिन पाँच बजे से तैयारी करने की चिंता अलग होती है । शहरों के पोलिंग स्टेशनों पर प्राय: राजनितिक दलों के लोग ठीक ठाक व्यवस्था कर देते हैं हालाँकि प्रशासन के स्पष्ट निर्देश होते हैं कि पोलिंग पार्टी द्वारा किसी राजनितिक दल से कोई सम्पर्क न रखा जाये।

हर चुनाव की रिहर्सल में पोलिंग स्टाफ रिटर्निंग आफिसर से पैसे की जगह रहने खाने की सही व्यवस्था करने की मांग करता है लेकिन सिवाय लोलीपोप के उन्हें मिलता कुछ नही है बस यही एक मुख्य वजह है कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी से बचने के प्रयासों की। इस बारे में मजदूर मोर्चा को कई सरकारी कर्मचारियों ने अपने अपने अनुभव सुनाये कुछ कर्मचारियों जिनकी ड्यूटी एक बार सन 2015 के पंचायत चुनावों में बल्लभगढ़ के गाँव अटाली में थी जहाँ छह पोलिंग बूथ थे जिन पर पाँच से छह कर्मचारियों की ड्यूटी थी इनमे से अधिकांश कर्मचारियों को न तो किसी ने खाना दिया और न ही सोने के लिए बिस्तर मिले जिस कारण पोलिंग पार्टी को रात भर भूखे पेट सर्द रात जैसे तैसे गुजारनी पड़ी । पंचायत के चुनावों में हालाँकि पंच व सरपंच पद के उम्मीदवार पोलिंग पार्टी से तालमेल करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं लेकिन पोलिंग पार्टी के लिए चुनाव की निष्पक्षता बनाये रखने के लिए किसी भी पक्ष या व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना उनकी मजबूरी होती हैं । विधानसभा या लोक सभा के चुनावों में स्थिति थोड़ी अलग होती है यहाँ उम्मीदवारों के प्रतिनिधि पोलिंग पार्टी की रहने व पीने खाने की व्यवस्था ठीक से कर देते हैं जिसके लिए वे पोलिंग पार्टी से अपने उम्मीदवार के लिए कुछ पाने की कोशिश करते हैं इसलिए पोलिंग पार्टी को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है । ऐसा ही एक अनुभव एक पोलिंग पार्टी के सदस्यों ने बताया कि उनकी ड्यूटी पिछले विधानसभा चुनावों में लक्कड़पुर में लगी थी वहां पर महेंदर प्रताप के लोगों ने रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और तो और नाश्ता भी दूध जलेबी का करवाया गया था ।

इन सभी परेशानियों के बाद शुरू होती है चुनाव की प्रक्रिया जिसका सुचारू रूप से सम्पन्न करना किसी युद्ध से कम नहीं होता है पोलिंग बूथ पर नियुक्त विभिन्न पार्टियों व प्रत्यासियों के एजेंट सबसे अधिक बदमाशी करते हैं । वे अपने प्रत्याशी के प्रति वफादारी का कोई मैका नही चूकना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें पहले ही मेहताना मिल चुका होता है । इस वफादारी के चलते वे फर्जी मतदान कराने का पूरा प्रयास करते हैं जिस कारण पोलिंग बूथ का माहौल सबसे अधिक खराब होता है जो पोलिंग पार्टी विशेषकर पीठासीन अधिकारी के लिए के चुनौती होता है जिससे निपटना आसान नही होता है यदि कोई अधिकारी सख्ती करता है तो ये एजेंट तुरंत ही पोलिंग पार्टी या पीठासीन अधिकारी पर किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आरोप या मतदान को धीमा चलने या फिर मतदान प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगा देते हैं । कई बार तो ये लोग बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर इवीएम को ही कब्जा लेते हैं और यदि कोई पीठासीन अधिकारी इस बारे में शिकायत करता भी है तो अधिकारी बजाए कुछ प्रबंध करने के जैसे चल रहा वैसे ही चलाने की बात कह देते हैं। प्रशासनिक अधिकारी पोलिंग पार्टी को रिहर्सल के दौरान ऐसी परिस्थिति के लिए इशारों में पहले ही आगाह करते हुए चेतावनी दे देते हैं कि किसी को ज्यादा कानूनबाज बनने की जरुरत नही है अन्यथा वे मुश्किल में फंस जायेंगे इसलिए कोई भी पीठासीन अधिकारी कोई जोखिम मोल नही लेता है हाँ यदि कहीं कोई बड़ी घटना घट जाये तो वहां थोड़ी बहुत कार्रवाई किया जाना प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरी बन जाती है अन्यथा बहुत कुछ दबंग प्रत्याशी की मर्जी अनुसार ही होता है और यह सब उन पुलिस वालों के सामने होता है जिनकी ड्यूटी पोलिंग बूथ पर लगी होती है ।

पोलिंग समाप्त होने के पश्चात कागजी कार्रवाई बहुत उबाऊ व जटिल होती है जिससे सुलझे हुए पीठासीन अधिकारी भी घबराते हैं। चुनाव प्रक्रिया के समाप्त होने के पश्चात बीसियों तरह के प्रपत्र व लिफाफे होते हैं जिनमे अधिकांश केवल औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं जिनमे पोलिंग पार्टी का घंटों का समय यूँही खराब होता है। फिर एक रूट की सभी पोलिंग पार्टियाँ उसी बस से वापिस आती हैं जिससे वो गई थी इसमें एक भी पोलिंग पार्टी द्वारा समाप्ति की औपचारिकतायें पूरी न कर पाने के कारण सभी पार्टियाँ लेट हो जाती हैं । गंतव्य स्थान पर पहुँच कर पोलिंग पार्टी के लिए सामान व दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया भी बहुत कष्टकारी होती है जिसमे घंटों का समय लग जाता है दो दिन से भूखी प्यासी व बुरी तरह से थकी हुई पोलिंग पार्टी जिसमे से भी एक दो पोलिंग आफिसर तो बहाने बना कर पहले ही खिसक चुके होते हैं , बिलकुल टूट जाती है । इस तरह से सामान को जमा कारते करते रात के एक और दो तक बज जाते हैं और जब तक प्रशासन द्वारा पोलिंग पार्टियों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए जो दो चार बस मंगाई होती हैं वे जा चुकी होती हैं ये बस भी मुख्य मुख्य स्थानों तक के लिए ही होती हैं । इस तरह से लगभग अड़तालीस घंटे की अत्यधिक तनावपूर्ण चुनावी ड्यूटी भूखे प्यासे बिना सोये देने से बचने के लिए कर्मचारी हर प्रयास करते हैं ।

प्राइवेट स्कूलों की 636 बसें व 1000 शिक्षक चुनाव ड्यूटी पर

सरकारी स्कूल बर्बाद करने के बाद खट्टर सरकार प्राइवेटों को भी नहीं बख्शेगी

फ़रीदाबाद (म.मो.) लगता है सरकार ने पूरी तरह से ठान लिया है कि शिक्षा का बेड़ागर्क करके छोड़ना है; क्योंकि पढ़े-लिखे युवा वर्ग के लोग रोज़गार मांगते हैं और उच्च स्तरीय बहस भी करने लगते हैं। तरकीब यह अपनाई जा रही है कि न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके लिये सरकार ने अपने तमाम शिक्षण संस्थानों प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज और युनिवर्सिटी तक को रसातल में पहुंचा दिया है। इनमें न शिक्षक हैं न शिक्षण व्यवस्था।

इससे आजिज साधन-सम्पन्न लोगों ने प्राइवेट स्कूलों का रुख किया। शिक्षा का यह व्यापार अच्छा-खासा फ़लने-फूलने लगा। शिक्षा व्यापारियों की आमदनी के साथ-साथ इनमें पढने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या व स्तर भी बढने लगा। लेकिन ये स्कूल भी अब सरकार की आंख में चुभने लगे। इनकी पढाई खराब करने के लिये अब सरकार ने दादागिरी दिखाते हुए शहर के प्राइवेट स्कूलों से करीब एक हज़ार शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी के लिये बुला लिया है। इस ड्यूटी से पूर्व रिहर्सल व मीटिंगों के जो दौर चलते हैं, उनमें करीब एक सप्ताह बर्बाद हो जाता है।

अब से पहले इस काम के लिये केवल सरकारी शिक्षकों को ही रगड़ा जाता था। ज़िले भर के दर्जनों शिक्षक तो स्थाई रूप से चुनाव कार्यालय के हवाले कर दिये जाते हैं। वे महीनों क्या बरसों तक स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाते। लेकिन जब स्कूलों में ही मास्टरों के हज़ारों पद खाली पड़े हैं तो सरकार की गिद्ध-दृष्टि उन प्राइवेट स्कूलों पर पड़ी जो पूर्णतया छात्रों के अभिभावकों से वसूली गयी फ़ीस के दम पर चल रहे हैं। सरकार का तर्क है कि चुनाव एक लोकतंत्रीय देश का महापर्व है, इसके लिये देश के सभी संसाधनों को कुछ दिन के लिये झोंका जा सकता है। लेकिन यह महापर्व तो अब पांच साल में कई बार आने लगा है। जो सरकार लाखों-करोड़ की बर्बादी अन्यथा कर देती है वह इस काम के लिये क्यों नहीं स्थाई व्यवस्था करती? शिक्षण संस्थानों के अलावा अपने विभागों में आधे से अधिक पड़े रिक्त स्थानों को क्यों नहीं भरती?

सरकार का यह भी तर्क है कि उसके पास किसी भी निजी संस्थान को राष्ट्रीय सेवाओं हेतु अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार है। सरकार अपने अधिकार की बात तो करती है लेकिन नागरिकों के अधिकारों को भूल जाती है। शिक्षा का अधिकार भी तो इसी देश के कानून ने दिया है, उसकी बात क्यों नहीं करती सरकार? जिस तरह से सरकार जनता के अधिकारों का दमन कर रही है, वह जनता को उकसा कर सरकार का मुकाबला करने की ओर धकेल रही है। तमाम शिक्षक व कर्मचारी संघ जो आये दिन जेल भरो आन्दोलन की नकली बातें करते हैं, ऐसे मौकों पर क्यों नहीं जेल भरते? अभी चार माह बाद फ़िर चुनाव का पर्व आयेगा। क्यों नहीं तमाम सरकारी कर्मचारी संगठन अपने तमाम महकमों में रिक्त पड़े स्थानों को भरने का अल्टीमेटम देते? सरकार को स्पष्ट शब्दों में बताया जा सकता है कि यदि दिये समय में रिक्तियां नहीं भरी जाती तो वे आगामी किसी भी चुनाव में ड्यूटी देने को बाध्य नहीं होंगे। पता चल जायेगा सरकार में जितना दम है और कर्मचारी संगठनों में कितना?

निजी स्कूलों ने छात्रों से वसूले पैसे से जो बसें खरीदी हैं, उनका दुरुपयोग समय-समय पर सरकारें करती आई हैं। कभी रैलियों के लिये भीड़ ढोने के लिये तो कभी नेताओं की बेगार के लिये। इस चुनाव में ज़िला प्रशासन ने अपने क्षेत्र में पड़ने वाली 6 विधान सभा सीटों की चुनाव ड्यूटी के लिये प्राइवेट स्कूलों की 636 बसों को 11 मई को ही कब्ज़े में ले लिया। ये बसें 12 मई को ड्यूटी करके रात करीब बारह, एक या दो बजे तक फ़ारिग हो पायेंगी। ऐसे में स्पष्ट है कि 13 मई को भी ड्राइवर-कन्डक्टर स्कूल की ड्यूटी नहीं कर पायेंगे। गनीमत यह मानो कि 12 मई का रविवार है वरना बच्चों को तीन दिन तक बसें व शिक्षक उपलब्ध नहीं होने वाले थे। परन्तु जनविरोधी सरकार को इससे क्या लेना-देना।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**